भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न सं. 97
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 03 फरवरी**,** 2025/14 माघ**,**1946 (शक) को दिया जाना है)

## बढ़ती कीमतें और वेतन में स्थिरता

97. **श्री हमदुल्ला सईद**:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार बढ़ती कीमतों और वेतन में स्थिरता की चिंता से अवगत है जिसके कारण उपभोग वृद्धि प्रभावित हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोग और आर्थिक विकास के समर्थन हेतु प्रमुख क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, वेतन वृद्धि में सुधार लाने और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं ?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

(क) वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) के लिए वर्ष 2023-24 की तुलना में स्थिर कीमतों पर 7.3 प्रतिशत और चालू कीमतों पर 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने का अनुमान है।

(ख) सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें प्रमुख खाद्य वस्तुओं के बफर का निर्माण, आवधिक रूप से इन वस्तुओं को खुले बाजार में जारी करना, घरेलू खाद्य उपलब्धता बढ़ाने के लिए व्यापार नीतियों को अपनाना, स्टॉक सीमा निर्धारित और संशोधित करके जमाखोरी को रोकना और विनिर्दिष्ट खुदरा दुकानों के माध्यम से सब्सिडी कीमतों पर चुनिंदा खाद्य पदार्थों का वितरण करना शामिल है। अवसंरचना के निर्माण, कौशल विकास, मानव संसाधन विकास और रोजगार सृजन पर सरकार द्वारा बल दिए जाने से रोजगार और आर्थिक विकास के संवर्धन और इस तरह घरेलू आय और उपभोग में सुधार होने की संभावना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कारोबार में सुगमता और सहायता के लिए किए गए उपायों से कारोबार उद्यमों तथा अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को निर्धारित, समीक्षा और संशोधित करती है। इसके अलावा, रोजगार और विकास पर सरकार का ध्यान सामान्य रूप से श्रम बाजार की स्थितियों को मजबूत करता है।

*** ****